सिद्धारमैया ने अखबारों में ऐड देकर मोदी को दी बहस की चुनौती

बेंगलुरु 7 मई (ए)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहस के लिए खुली चेतावनी देते हुए अखबारों में इसके विज्ञापन दिए हैं। सिद्धारमैया ने बेंगलुरु से निकलने वाले दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवाया व पीएम मोदी और पूर्व सीएम बी. एस. येदियुरप्पा को चुनौती दी कि हम बहस के लिए तैयार हैं, बस समय और तारीख आप बता दें। कर्नाटक सीएम ने कहा कि पीएम मोदी राज्य में रैलियां करके लोगों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें प्लेटफॉर्म पर खुली बहस के लिए चुनौती देता हूं, क्या पीएम इसे स्वीकार करेंगे। बता दें कि 12 मई को कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है। जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 15 मिनट संसद में बोलने का समय मांगा वहीं पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष बिना पेपर और मोबाइल देखे बोलते हैं तो इससे अच्छा क्या होगा।

श्रीनगर में 'दरबार मूव' प्रथा के तहत खुला जम्मू-कश्मीर सचिवालय

श्रीनगर 7 मई (ए)। जम्मू - कश्मीर सरकार ने आज 150 वर्ष पुरानी प्रथा 'दरबार मूव' के तहत अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में अपने कार्यालय खोलें। सिविल सचिवालय के अलावा राज भवन , पुलिस मुख्यालय और विभिन्न कमीशन सहित कई कार्यालय आज सुबह यहां खोलें गए। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को परंपरा के अनुसार सिविल सचिवालय परिसर में पुलिस दल ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ' दरबार मूव ' प्रथा के तहत राज्य की सरकार सिंदयों में छह माह जम्मू और गिंमयों में छह माह श्रीनगर से अपने कार्यालय स्थापित करती है। इसकी शुरुआत महाराजा गुलाब सिंह ने राज्य के दोनों क्षेत्रों में उग्र मौसम से बचने के लिए वर्ष 1872 में की थी। बहराल , इस प्रथा को स्वतंत्रता के बाद भी जारी रखा गया ताकि कश्मीर और जम्मू के दोनों क्षेत्रों को छह-छह माह शासन का लाभ मिल सके।

केजरीवाल की जुबान फिसली, उत्तराखंड को बोल गए उत्तराप्रचंड

नई दिल्ली 7 मई (ए)। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का रविवार को एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद ट्विटर पर केजरीवाल काफी ट्रोल हुए, लोगों ने उनके वीडियो पर खूब मजे लिए। वायरल वीडियो में केजरीवाल भाजपा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सीएम कहते हैं- ये अब सरकारें तोड़ेंगे, गिराएंगे। पहले इन्होंने अरुणाचल प्रदेश की सरकार तोड़ी फिर उत्तराप्रचंड की तोड़ दी। दरअसल केजरीवाल इतनी जल्दबाजी में बोल रहे थे कि उनकी जुबान फिसल गई और उत्तराखंड की जगह उत्तराप्रचंड बोल गए। लोगों ने दिल्ली सीएम की खूब खिंचाई की और कहा कि शुक्र है आपकी सरकार वहां नहीं है वर्ना उत्तराखंड सच में उत्तराप्रचंड बन जाता।

मोदी ने पूछा- क्या सारी बेरोजगारी पिछले चार साल में पैदा हुई है

नई दिल्ली 7 मई (ए)। रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि जो खुद निराश है, वे देश में निराशा पैदा कर रहे हैं। साथ ही मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने रेलवे से लेकर राजमार्ग और डिजिटल क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक आधारभूत ढांचे के विकास के लिये व्यापक निवेश किये हैं जिससे रोजगार के काफी अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को 'नरेन्द्र मोदी एप' के जरिये संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी के पास अपने कार्यकाल की अच्छी बातें बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। कांग्रेस ने 60 साल राज किया, लेकिन काम कुछ नहीं किया, इसलिए उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि वह (कांग्रेस) अपने 60 वर्षों के कार्यकाल की कुछ अच्छी बातें बता सकती थी लेकिन कुछ भी नहीं है, इसलिये झूठ फैला रहे हैं और झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सवाल किया कि क्या देश में सारी बेरोजगारी पिछले चार साल में आई है? इससे पहले उनकी (कांग्रेस की) सरकार 10 साल रही लेकिन कुछ नहीं किया गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या बड़े पैमाने पर यह बेरोजगारी हमें विरासत में नहीं मिली? प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने ऐसे कई काम किए हैं, जिनसे रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की कई एजेंसियों ने भारत की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि युवाओं की आशाओं, आकांक्षाओं को केवल एक रास्ते से पूरा नहीं किया जा सकता। इसीलिये उनकी सरकार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ ही पर्सनल सेक्टर पर भी बल दे रही है, इस क्षेत्र में पूंजी लगा रही है। मोदी ने कहा, हमारी सरकार ने रेलवे से लेकर राजमार्ग और डिजिटल क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक आधारभूत ढांचे के विकास के लिये व्यापक निवेश किये हैं। जब आधारभूत ढांचे के विकास पर इतने बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा हो, कार्य हो रहा हो.. तब क्या रोजगार पैदा नहीं होगा? ये सभी क्षेत्र श्रम से जुड़े हैं।

हवाई में ज्वालामुखी फटने से 200 फुट तक उठा लावा, 21 घर तबाह

वॉशिंगटन 7 मई (ए.)। अमरीकी राज्य हवाई में किलाउए ज्वालामुखी का कहर जारी है। ज्वालामुखी के ताजा विस्फोट से 21 घर तबाह हो गए । वैज्ञानिकों के अनुसार विस्फोट इतना तेज है कि लावा हवा में 61 मीटर (200 फुट) ऊपर तक उछल रहा है। ज्वालामुखी फटने के कारण घर से सुरक्षित स्थानों पर ले जाए गए 1700 से अधिक लोगों के जल्द वापसी की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। हवाई के अधिकारियों ने बताया कि तबाह हुए घर लीलानी एस्टेट उपखंड में हैं जहां ज्वालामुखी फटने के कारण जगह-जगह जमीन फट गई है जिससे विषाक्त गैस और भाप निकल रहा है। हवाई की प्रवक्ता ने जैनेट सैंडर ने कहा कि आंकड़ों में बदलाव आ सकता है। यह पीड़ादायक है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे वोल्कैनलॉजिस्ट वेंडी स्टोवैल ने कहा कि अंदर अभी और मैग्मा है जो अभी निकल सकता है। जब तक मैग्मा अंदर मौजूद है तब तक यह निकलता रहेगा।

महाभियोग पर नायडू के फैसले के खिलाफ आज होगी सुनवाई

■ नोटिस खारिज करने को कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

नई दिल्ली ,07 मई (ए)। राज्यसभा के सभापति द्वारा चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस खारिज किये जाने को चुनौती देने वाली विपक्षी सांसदों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अधिवक्ताओं से कहा कि वे कल उसके समक्ष आएं, तभी इस मुद्दे को देखेंगे। गौरतलब है कि सभापति ने यह कहते हुए नोटिस खारिज कर दिया था कि न्यायमूर्ति मिश्रा के खिलाफ किसी प्रकार के कदाचार की पुष्टि नहीं हुई है। सभापति की इसी व्यवस्था को विपक्ष के दो सांसदों ने आज न्यायालय में चुनौती दी है।

महाभियोग नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सांसदों में शामिल वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति जे . चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति एस . के . कौल की पीठ से तत्काल सुनवाई के लिए यचिका को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। पीठ ने मास्टर ऑफ रोस्टर के संबंध में संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए सिब्बल और अधिवक्ता प्रशांत भूषण से कहा कि वह तत्काल सुनवाई के लिए याचिका प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखें। यह याचिका दायर करने वाले सांसदों में पंजाब से कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा और गुजरात से अमी हर्षदराय याज्ञनिक शामिल हैं। दोनों न्यायमूर्ति चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति कौल ने आपस में विचार किया और सिब्बल तथा भूषण से कहा कि वे कल उनके समक्ष आएं , ताकि इस मुद्दे पर गौर किया जा सके। सिब्बल ने कहा कि मास्टर ऑफ रोस्टर के संबंध में संविधान पीठ का फैसला उन्हें ज्ञात है , लेकिन महाभियोग नोटिस प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ होने के कारण शीर्ष अदालत का वरिष्ठतम न्यायाधीश तत्काल सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध कर सकता है।

प्रक्रिया की है पूरी जानकारी: सिब्बल

सिब्बल ने कहा कि उन्हें प्रक्रिया की जानकारी है, लेकिन इसे किसी अन्य के समक्ष नहीं रखा जा सकता। एक व्यक्ति अपने ही मुकदमे में न्यायाधीश नहीं हो सकता। वह सिर्फ तत्काल सुनवाई का अनुरोध कर रहे हैं, उन्होंने कोई अंतरिम राहत नहीं मांगी है। उन्होंने कहा कि प्रधान न्यायाधीश सूचीबद्ध करने का आदेश नहीं दे सकते हैं, ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही कुछ आदेश देना होगा क्योंकि यह संवैधानिक महत्व का मामला है। सिब्बल के अनुसार , पहले कभी ऐसे हालात पैदा नहीं हुये और न्यायालय को आदेश देना चाहिए कि मामले की सुनवाई कौन करेगा और कैसे करेगा। न्यायमूर्ति कौल ने याचिका का मसौदा तैयार करने वाले सिब्बल से पूछा कि क्या याचिका का पंजीकरण हो गया है ? सिब्बल ने जवाब दिया कि उन्होंने याचिका रजिस्ट्री में दाखिल की है, लेकिन वह इसे पंजीकृत करने के इच्छुक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस न्यायालय की प्रक्रिया बहुत सरल है। वह पिछले 45 वर्ष से यहां वकालत कर रहे हैं। इस मामले में रजिस्ट्रार प्रधान न्यायाधीश से आदेश नहीं ले सकते। प्रधान न्यायाधीश मास्टर ऑफरोस्टर के अपने अधिकार रजिस्ट्रार को नहीं सौंप सकते हैं। वह न्यायमूर्ति चेलामेश्वर से सिर्फ इस पर विचार करने का अनुरोध कर रहे हैं।

चेलामेश्वर ने क्या कहा

न्यायमूर्ति चेलामेश्वर ने उत्तर दिया, श्श्मैं सेवा निवृत्त होने वाला हूं। सिब्बल ने न्यायालय से याचिका पर कब सुनवाई होगी और कौन करेगा इस संबंध में आदेश देने का अनुरोध किया। सिब्बल के साथ पेश हुए अधिवक्ता भूषण ने कहा कि नियमों के अनुसार , प्रधान न्यायाधीश कोई भी आदेश देने में अक्षम हैं और सिर्फ वरिष्ठतम न्यायाधीश ही मामले को सूचीबद्ध करने का आदेश दे सकता है। राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा को पद से हटाने के संबंध में विपक्ष की ओर से दिये गये नोटिस को 23 अप्रैल को खारिज कर दिया था। ऐसा पहली बार हुआ है जब मौजूदा प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग नोटिस दिया गया था।

जल्द कार्य योजना तैयार करेगा वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली ,07 मई (ए)। वाणिज्य मंत्रालय ने अफ्रीका के साथ व्यापार को गति देने के लिए व्यापक योजना तैयार करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने बताया कि दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा के लिए अफ्रीका के विभिन्न भागों में कई गतिविधियां शुरू की गई हैं। दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार फिलहाल संभावनाओं के 'अपेक्षाकृत' कम है। प्रभु ने कहा कि नए बाजार तलाशने की हमारी रणनीति के तहत हम अफ्रीका के साथ लगातार जुड़ रहे हैं। वहां निर्यात के लिए काफी गुंजाइश है, हमने अफ्रीका से निर्यात और आयात को गति देने के लिए कार्य योजना तैयार करने का फैसला किया है।'' उन्होंने कहा कि व्यापार और निवेश पर वार्ता को गति देने के लिए हमने उसे पांच भागों- पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिण तथा मध्य में विभाजित किया है। प्रभु के अनुसार पूर्वी भाग में बातचीत पूरी हो गई है और जल्दी ही अल्जीरिया तथा नाइजीरिया में भी इस प्रकार की बातचीत शुरू की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इसके पीछे सोच नए बाजार की तलाश है। हम उनके साथ नियमित बैठक कर रहे हैं, अफ्रीका के साथ व्यापार अपेक्षाकृत कम है।

स्थिति बेहतर होने पर अन्य हिस्सों से भी हटा लिया जाएगा आफस्पा : रिजिजू

नयी दिल्ली 7 मई (ए)। केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संघर्ष वाले क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को विशेषाधिकार प्रदान करने वाले आफस्पा कानून के संदर्भ में कहा कि स्थिति बेहतर होने पर अन्य हिस्से से भी इस कानून को हटाया जा सकता है। रिजिजू ने कहा कि मौजूदा समय में जारी नगा शांति वार्ता पर पूरी ईमानदारी से काम किया जा रहा है और इसका नतीजा सकारात्मक होगा लेकिन उन्होंने अंतिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कोई समय-सीमा बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि, 'पिछले चार साल में पूर्वोत्तर में सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है और कई इलाकों से अफस्पा हटा लिया गया है। हमें उम्मीद है कि और बेहतर होने पर आने वाले समय में अन्य हिस्सों से भी इसे हटा लिया जाएगा।' सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) को मेघालय से पूरी तरह और अरुणाचल प्रदेश से आंशिक तौर पर हटा लिया गया है। यह कानून अभी नगालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों में प्रभावी है। यह विवादित कानून जम्मू-कश्मीर में लागू है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रिजिजू ने यह भी कहा कि सुरक्षा स्थिति में सुधार होने के बाद विवादास्पद आफस्पा कानून नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और अन्य इलाकों से हटाया जाएगा। नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल आफ नगालैंड (एनएससीएन-आईएम) के आइजक मुइवा गुट के साथ सरकारी वार्ताकार की बातचीत का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार नगा और पूर्वोत्तर के मसलों के प्रति अति संवेदनशील है। ताकि इसका परिणाम सकारात्मक हो।' अंतिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए संभावित तारीखों के बारे में पूछे जाने पर रिजिजू ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में तीन अगस्त 2015 को एनएससीएन आईएम के महासचिव थुइंगालेंग मुइवा और सरकार के वार्ताकार आर एन रवि के बीच समझौते की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किया गया था।

दिल्ली मेट्रो के अश्लील वीडियो भी होते हैं वायरल

नई दिल्ली 7 मई (ए)। दिल्ली मेट्रो की भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें यह साफ देखा जा सकता है कि प्रेमी युगल अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। वह सीमा रेखा पार कर जाते हैं और स्थिति अश्लीलता फैलाने जैसी बन जाती है। दरअसल सार्वजनिक रूप से प्रेम, वह भी बिना किसी तरह का लिहाज किए सामान्य नहीं है।

आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं वीडियो : इस कारण इसे अश्लील माना जाता है। दिल्ली मेट्रो में खुलकर प्यार करने के कई वीडियो सोशल मीडिया में आज भी मौजूद हैं। एक बार तो एक जोड़े ने सारी हदें पार कर दी थी और ऐसा कृत्य किया था जो बेडरूम में भी शोभनीय नहीं होता। इस जोड़े की वीडियो को मेट्रो कर्मचारियों ने कंट्रोल रूम में देखा था और यह वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो गई थी। इसकी खबर भी मीडिया में खूब चली थी। बड़ी बात यह है कि कोलकाता की घटना से दिल्ली को सोचने का मौका मिला है कि यदि इस तरह की हरकते हीं मेट्रो के भीतर नहीं हो तो प्रेमी युगल की पिटाई और बाहर धकेलने जैसी घटना तो होगी ही नहीं। बेपरवाह युवाओं को यह समझना चाहिए।

पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बटन का करें उपयोग : दिल्ली मेट्रो की ट्रेनों में पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बटन लगाया गया है। किसी भी आपात स्थिति में इस बटन का प्रयोग करके यात्री अपनी दिक्कत को बता सकते हैं। सुरक्षा संबंधी मामलों के साथ यदि अश्लीलता फैलाने जैसा मामला हो तो भी इस बटन को दबाकर कोई भी शिकायत कर सकता है। इसके बाद मेट्रो की तरफ से शिकायत सुनने के बाद तत्काल एक्शन लिया जाएगा।

भारतीयों के लिए जिन्ना आदर्श नहीं हो सकते

नई दिल्ली ,07 मई (ए)। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में मोहम्मद अली जिन्ना की एक तस्वीर को लेकर चल रहे विवाद के बीच भाजपा ने आज स्पष्ट किया कि जिन्ना हिन्दू, मुसलमानों समेत किसी भारतीय का आदर्श नहीं हो सकते है और इस बारे में विवाद पर विराम लगाया जाना चाहिए।

भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने यहां कहा कि देश के बंटवारे के लिये मो. अली जिन्ना जिम्मेदार है, बंटवारे के बाद हजारों की संख्या में लोग मारे गए, इसके लिये भी जिन्ना जिम्मेदार है। जिन्ना देश में हिन्दू, मुसलमान सहित किसी भी भारतीय के आदर्श नहीं हो सकते है। कोई जिन्ना को पसंद नहीं करता है।एएमयू में जिन्ना की तस्वीर के विषय पर उन्होंने सवाल किया कि क्या यूरोप में हिटलर की तस्वीर लगायी जा सकती है? उन्होंने कहा कि भारत के बंटवारे के बाद कई चीजे बंटी और ऐसे में अगर एएमयू में जिन्ना की तस्वीर थी, तब उसे पाकिस्तानी उच्चायोग को सौंपी जा सकती थी। हुसैन ने कहा कि भाजपा चाहती है कि एएमयू में बच्चे पढ़े, परीक्षा दें, तरक्की करें। उन्होंने कहा कि बच्चों के आदर्श मौलाना अबुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम, विस्मिल्ला खां, अशफाकुल्ला खां हैं, लेकिन जिन्ना भारतीयों के आदर्श नहीं हो सकते।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी एएमयू के प्रशासन और छात्रों को 'बेवजह का विवाद' खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि क्योंकि पाकिस्तान के संस्थापक न तो भारत के आदर्श हैं और न ही भारतीय मुसलमानों के आदर्श हैं। नकवी ने कहा कि इस बात को यहीं खत्म करना चाहिए और विश्वविद्यालय की गरिमा का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए।

गौरतलब है कि एएमयू के यूनियन हॉल में लगी जिन्ना की तस्वीर को लेकर पिछले दिनों अलीगढ़ के भाजपा सांसद सतीश गौतम ने कुलपति तारिक मंसूर को पत्र लिखा था। इसके बाद ही इस विवाद की शुरूआत हुई। इसी मामले को लेकर हिन्दू युवा वाहिनी के कुछ कार्यकर्ताओं ने गत दो मई को परिसर में घुसकर हंगामा और नारेबाजी की थी। इस हंगामे को लेकर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

वहीं नकवी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में स्वीकृत 'प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम' के तहत देश भर में वक्फसंपत्तियों का भी विकास होगा, ताकि मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण को गति दी जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ संपत्तियों के लीज संबंधी नियमों की समीक्षा के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की गई है ताकि इन नियमों को लेकर अधिक स्पष्टता हो सके। बता दें कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) का प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के रूप में नामकरण करने और पुनर्गठन की मंजूरी दी।

अमृत मेडीकल स्टोरों में रियायती दरों पर मिल रहीं दवाइयां : नड्डा

कांगड़ा 7 मई (ए)। देश के स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा रविवार को अचानक कांगड़ा में पूर्व शिक्षा मंत्री पंडित शिव कुमार जोकि आजकल अस्वस्थ चल रहे हैं, उनका हालचाल पूछने पूर्व मंत्री जी.एस. बाली के निवास पर पहुंचे जोकि पंडित शिव कुमार के समधी हैं। इसके बाद वह पूर्व परिवहन, खाद्य एवं आपूर्ति व तकनीकी मंत्री जी.एस. बाली से एक शिष्टचारिक भेंट में मिले। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि इस समय देश में 134 अमृत मैडीकल स्टोर दवाइयों के लिए हैं, जिसमें से 2 हिमाचल (शिमला आई.जी.एम.सी. व डा. राजेंद्र प्रसाद मैडीकल कालेज) में हैं। उन्होंने बताया कि इसमें 588 लोगों को रोजगार मिला है और 6.29 लाख करोड़ की दवाइयां रोगियों को मात्र 2.8 लाख करोड़ रुपए में दी गईं, जिससे रोगियों को 3.46 करोड़ लाख का फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि इन स्टोरों पर हम रियायती दरों पर दवाइयां दे रहे हैं। आयुष्मान भारत के तहत 90 प्रतिशत एस.सी.सी. डेटा की वैरीफिकेशन उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत देश में 90 प्रतिशत एस.सी.सी. डेटा की वैरीफिकेशन कर लिया है और बाकी पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत कौन-कौन सी सुविधाएं दी जा सकती हैं जैसे कि आप्रेशन आदि के बारे में काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ सरकारी व प्राइवेट में क्या-क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं। उसके अनुसार ही इंपलीमैंट होगा। इस मौके पर आर.एस. बाली युवा नेता, पूर्व विधायक संजय चौधरी, कृपाल परमार, विक्रम जरयाल व कार्तिक पाधा आदि कई नेता मौजूद थे।

6 साल में भारत में सबसे ज्यादा गोद ली गईं लड़कियां, महाराष्ट्र रहा टॉप पर

नई दिल्ली 7 मई (ए)। भारत में पिछले छह वर्षों में गोद लिए गए बच्चों में करीब 60 प्रतिशत लड़कियां थीं। इनमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर रहा जहां हाल में सबसे ज्यादा बच्चे गोद लिए गए। आंकड़े के अनुसार 2017-18 में गोद लिए गए कुल 3,276 बच्चों में से 1,858 लड़कियां थीं जबकि लड़कों की संख्या 1,418 थी। सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (कारा) ने एक आरटीआई आवेदन के जवाब में बताया कि 2012 के बाद से हर राज्य में गोद लिए गए बच्चों की संख्या के लिहाज से महाराष्ट्र सबसे ऊपर था। 2017 में राज्य में गोद लिए गए कुल 642 बच्चों में से 353 लड़कियां थीं।

ये देश भी पीछे नहीं : महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बच्चों के गोद लिए जाने का कारण वहां कई अडोप्शन एजेंसियां होना है। दूसरा स्थान कर्नाटक का रहा जहां गोद लिए गए कुल 286 बच्चों में से 167 लड़कियां थीं। पश्चिम बंगाल (203) का स्थान आता है। आरटीआई आवेदन के जवाब में बताया गया कि 2017-18 में गोद लिए जाने के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिका, इटली, फ्रांस और स्पेन के परिवार आगे रहे।

2016-17 में भारत के अंदर गोद लिए गए कुल 3,210 बच्चों में से 1,915 लड़कियां थीं। पिछले पांच साल के आंकड़ों से पता चला कि 59.77 प्रतिशत दंपतियों ने लड़कियां गोद लीं जबकि 40.23 प्रतिशत ने लड़के। कारा के सीईओ लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार ने कहा कि इससे पता चलता है कि चीजें अब बदल रही हैं। इसके अलावा लोगों को लगता है कि लड़कियों की देखरेख करना लड़कों की तुलना में ज्यादा आसान है और यह गोद लेने के समय लड़कियों के पक्ष में जाता है।

मौत के बाद सामने आई स्टीफन की अंतिम थ्योरी, ब्रह्मांड को लेकर खोला नया राज

वॉशिंगटन 7 मई (ए.)। दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग की मौत के डेढ़ महीने बाद 2 मई को कैम्ब्रिज ने उनकी नई थ्योरी को रिलीज किया है। उनकी मौत इसी साल 14 मार्च को हुई थी। उन्होंने ये थ्योरी मौत के 10 दिन पहले ही खत्म की थी। इस थ्योरी के जरिए उन्होंने अपनी पुरानी थ्योरी को गलत बताया है। इस थ्योरी में उन्होने ब्रह्मांड को लेकर खोला नया राज खोला है । इसमें बताया गया है कि ब्रह्मांड का कोई और

छोर भी हो सकता है।

वहीं उनकी पिछली थ्योरी में बताया गया था कि ब्रह्मांड अनंत है। उनकी नई थ्योरी को जर्नल ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स में पब्लिश किया गया है। हॉकिंग की पुरानी थ्योरी में संदेह पैदा हुआ था कि बिग बैंग के बाद एक नहीं बल्कि कई ब्रह्मांडों का निर्माण किया गया होगा। हॉकिंग की नई थ्योरी में कहा गया है कि अंतरिक्ष में ऐसी जगह होगी जहां धरती जैसा कोई सौरमंडल हो सकता है।

हो सकता है वहां डायनासोर हों, इंसान शिकार करते हों, ये कहना मुश्किल है कि वो बिलकुल धरती जैसा होगा। लेकिन वहां की जिंदगी मिलती-जुलती हो सकती है।साथ ही हॉकिंग ने अपनी पिछली थ्योरी को गलत बताते हुए लिखा है- बिग बैंग से पहले क्या था ये कोई नहीं बता सकता। अगर कोई दावा कर रहा है तो वो झूठ है. मैनें भी ऐसा दावा किया था, जो इस स्टडी में गलत साबित हुआ।

क्या है बिग-बैंग थ्योरी : इस थ्योरी में बताने की कोशिश की गई थी कि यह ब्रह्मांड कब और कैसे बना साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने इस थ्योरी को समझाते हुए कहा था कि करीब 15 अरब साल पहले भौतिक तत्व और ऊर्जा एक बिंदु में सिमटे हुए थे। फिर इस बिंदु ने फैलना शुरू किया। बिग बैंग, बम विस्फोट जैसा विस्फोट नहीं था बल्कि इसमें प्रारंभिक ब्रह्मांड के कण समूचे अंतरिक्ष में फैल गए और एक दूसरे से दूर भागने लगे।